Jagran City, Faridabad, 19/09/2025
Page No: 2, Size: 42.41cm × 17.22cm

एनएचआरसी ने लिया संज्ञान, ईएसआइसी प्रबंधन को नोटिस जारी

- दैनिक जागरण ने 9 सितंबर के अंक में प्रकाशित की थी खबर, कारपोरेशन चेयरमैन और मुख्य सचिव से मांगा जवाब
- मेडिकल कालेज में मरीजों को नहीं मिल रही सुविधाएं

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद : ईएसआइसी मेडिकल कालेज अस्पताल में व्याप्त कमियों और इस कारण मरीजों को होने वाली परेशानियों को दैनिक जागरण ने खबरों के माध्यम से खूब उजागर किया है। नौ सितंबर के अंक में सुबह से हो गई दोपहर, नहीं आए डाक्टर, मरीज करते रहे इंतजार शीर्षक से प्रकाशित रिपोर्ट पर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने संज्ञान लिया है। आयोग ने प्रदेश के मुख्य सचिव और ईएसआइ कारपोरेशन के चेयरमैन से इस मामले में दो सप्ताह में जवाब देने को कहा है। आयोग की ओर से भेजे गए नोटिस में ईएसआइसी अस्पताल में विशेषज्ञ चिकित्सकों के न होने का हवाला देते हुए मामले को गंभीर बताया गया है।

सुबह से हो गई दोपहर, नहीं आए डाक्टर, मरीज करते रहे इंतजार

दैनिक जागरण के नौ सितंबर के अंक में प्रकाशित खबर • जागरण

बता दें कि लंबे समय से एनआइटी तीन स्थित ईएसआइसी अस्पताल में विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी चल रही है। चिकित्सकों की कमी से स्वास्थ्य सेवाएं बिगड़ रही हैं और अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं। हर महीने अपने वेतन में से इलाज के नाम की राशि कटवाने के बाद भी ईएसआइ कार्डधारक स्वास्थ्य सेवा को तरस रहे हैं। इसी मुद्दे को दैनिक जागरण ने उठाया था। जागरण पड़ताल के दौरान अस्पताल के आपातकालीन विभाग की बिगड़ी व्यवस्था को लेकर भर्ती मरीजों से भी बातचीत की गई थी। मरीजों ने रोष जताया था कि उन्हें डाक्टर का इंतजार करते-करते घंटों लग जाते हैं, मगर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तब मेडिकल कालेज के डीन डा. कालीदास दत्तात्रेय ने विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी को स्वीकार करते हुए सुधार की बात कही थी और अनुबंध के तहत डाक्टरों की नियुक्ति करने को कहा था। अब देखते हैं कि एनएचआरसी के नोटिस जारी करने पर अस्पताल प्रबंधन क्या जवाब तैयार करते हैं और कमियों को दूर करने बारे क्या कदम उठाते हैं।

Free Press Journal, Mumbai, 19/09/2025
Page No: 7, Size: 23.68cm × 17.83cm

NHRC DEBUNKS CLAIMS | **Notice issued in response to a complaint of April 2023 by the Govandi Citizens' Welfare Forum, seeking NHRC's intervention**

Notices to BMC chief, ward officer, collector, CP over manual scavenging

Manoj Ramakrishnan
MUMBAI

The National Human Rights Commission (NHRC) has issued notices to the BMC chief, assistant municipal commissioner (M-East ward), district collector and the Commissioner of Police (CP), saying that the civic body is violating human rights by permitting manual scavengers to clean sewage drains with bare hands, risking their health and lives. The agencies have been asked to prepare a list of victims of manual scavenging in the ward and reply to the notice by October 24.

The notice was issued earlier this week in response to a complaint in April 2023 by the Govandi Citizens' Welfare Forum, seeking the commission's intervention in stopping blatant violation of laws forbidding manual scavenging, including the Prohibition of Employment of Manual Scavengers and their Rehabilitation Act, 2013.

Advocate Faiyaz Alam Shaikh, the convenor of the citizens' group, said they provided the commission photographs as proof that labourers were working in unsafe conditions in Kamala Rajan Nagar and Baiganwadi in M-East ward. Dinesh Berdia of Sangharsh, a group working for the abolition of manual scavenging and the caste-based exploitation involved in the work, said, "Govandi residents brought it to the notice of the commission, but it is happening all over Mumbai. Contractors entrust the work to subcontractors who hire unorganised labourers. They do not care about the lives or health of the workers and their families," said Berdia.

A family cleaning a storm water drain that has become a sewage channel -Manoj Ramakrishnan

The commission said that the BMC appoints contractors by inviting tenders for desilting of minor drains, road side drains and culverts by using manpower and machinery. The contractor removes silt and floating material from minor nullahs and road-side drains by deploying labourers and machinery as these are storm water outlets meant to carry rainwater discharge. However, human rights activists pointed out that in Mumbai storm water drains have become sewage lines, with illegal discharge of domestic and industrial waste.

In an earlier reply, the BMC had told the commission that desilting is undertaken by manpower with safety gear, such as hand gloves, helmets, reflecting jackets, safety shoes, with contractors penalised for lapses. In case the drains are difficult for cleaning equipment to access, contractors use labourers, but under precautions and safety advice of a medical officer.

The commission debunked the claims, saying that labourers were found cleaning gutters with bare hands and the authorities failed to explain this in their report dated August 25, 2023. The commission further stated that even if it was the contractors who employed labourers to clean the gutters, it does not absolve the principal employer (the BMC) of their liability for safeguarding the manual scavengers.

WHAT NHRC SAID

The commission said that there appears to be a violation of the 2013 law

It said the M-East ward has not replied to its show cause notice in May 2024, as to why a compensation of ₹50,000 each should not be given to manual scavengers for violation of their human rights

It said that failure to reply to the notice will lead to coercive process under the Protection of Human Rights Act, 1993

Dainik Jagran, Varanasi, 19/09/2025
Page No: 11, Size: 10.69cm × 17.14cm

गाजीपुर प्रकरण में मानवाधिकार आयोग ने दी डीजीपी व डीएम को नोटिस, मांगी रिपोर्ट

पुलिस लाठीचार्ज से भाजपा कार्यकर्ता सियाराम की मौत मामले का स्वतः संज्ञान लिया, दो सप्ताह में तलब की गई रिपोर्ट

जागरण संवाददाता, गाजीपुर : राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने नोनहरा पुलिस की पिटाई से भाजपा कार्यकर्ता सियाराम उपाध्याय की मौत के मामले का स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग ने पुलिस महानिदेशक व गाजीपुर के जिलाधिकारी को नोटिस जारी कर दो सप्ताह में रिपोर्ट तलब की है।

आयोग ने माना कि बिजली के खंभे लगाए जाने के विरोध में थाना परिसर में धरना देने के दौरान पुलिस लाठीचार्ज में सियाराम की मौत और कई अन्य लोगों के घायल होने की घटना गंभीर है। पूर्व आइपीएस अफसर अमिताभ ठाकुर ने भी मानवाधिकार आयोग से शिकायत की थी।

आयोग ने 12 सितंबर को प्रकाशित खबर का स्वतः संज्ञान लेते हुए रिपोर्ट मांगी है। उसने कहा है कि समाचार पत्रों में प्रकाशित बातें यदि सच हैं तो पीड़ितों के साथ मानवाधिकार का गंभीर उल्लंघन हुआ है। नोनहरा के गठिया गांव में बिजली का खंभा लगाने को लेकर गांव के ही ओंकार व अरविंद का अन्य के साथ विवाद चल रहा था। इस मुद्दे को लेकर भाजपा नेता विकास राय, राजेश राय बागी सहित करीब 50 लोग नौ सितंबर को नोनहरा थाना में धरना दे रहे थे। आरोप है कि मध्यरात्रि पुलिस ने लाइट बंद कर धरना दे रहे लोगों की पिटाई की थी। अधिक चोट लगने से चकरुकुंदीपुर निवासी दिव्यांग सियाराम उपाध्याय की मौत हो गई। मामले में मुख्यमंत्री के निर्देश पर एसपी डा. ईरज राजा ने थानाध्यक्ष वेंकटेश तिवारी समेत छह पुलिसकर्मियों को निलंबित करने के साथ पांच को लाइन हाजिर किया था।

डीएम अविनाश कुमार ने मजिस्ट्रियल जांच के लिए टीम गठित की। लोगों में पुलिसकर्मियों पर हत्या का मुकदमा दर्ज नहीं होने को लेकर नाराजगी थी।

Dainik Jagran, Ghazipur, 19/09/2025
Page No: 13, Size: 16.30cm × 12.83cm

गाजीपुर प्रकरण में मानवाधिकार आयोग ने डीजीपी व डीएम को नोटिस देकर मांगी रिपोर्ट

पुलिस लाठीचार्ज से भाजपा कार्यकर्ता सियाराम की मौत मामले का स्वतः संज्ञान लिया, दो सप्ताह में तलब की गई रिपोर्ट

जागरण संवाददाता, गाजीपुर : राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने नोनहरा पुलिस की पिटाई से भाजपा कार्यकर्ता सियाराम उपाध्याय की मौत के मामले का स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग ने पुलिस महानिदेशक व गाजीपुर के जिलाधिकारी को नोटिस जारी कर दो सप्ताह में रिपोर्ट तलब की है। आयोग ने माना कि बिजली के खंभे लगाए जाने के विरोध में थाना परिसर में धरना देने के दौरान पुलिस लाठीचार्ज में सियाराम की मौत और कई अन्य लोगों के घायल होने की घटना गंभीर है। पूर्व आइपीएस अफसर अमिताभ ठाकुर ने भी मानवाधिकार आयोग से शिकायत की थी। आयोग ने 12 सितंबर को प्रकाशित खबर का स्वतः संज्ञान लेते हुए रिपोर्ट मांगी है। उसने कहा है कि समाचार पत्रों में प्रकाशित बातें यदि सच हैं तो पीड़ितों के साथ मानवाधिकार का गंभीर उल्लंघन हुआ है। नोनहरा के गठिया गांव में बिजली का खंभा लगाने को लेकर गांव के ही ओंकार व अरविंद का अन्य के साथ विवाद चल रहा था। इस मुद्दे को लेकर भाजपा नेता विकास राय, राजेश राय बागी सहित करीब 50 लोग नौ सितंबर को नोनहरा थाना में धरना दे रहे थे। आरोप है कि मध्यरात्रि पुलिस ने लाइट बंद कर धरना दे रहे लोगों की पिटाई की थी। अधिक चोट लगने से चकरुकुंदीपुर निवासी दिव्यांग सियाराम उपाध्याय की मौत हो गई। मामले में मुख्यमंत्री के निर्देश पर एसपी डा. ईरज राजा ने थानाध्यक्ष वेंकटेश तिवारी समेत छह पुलिसकर्मियों को निलंबित करने के साथ पांच को लाइन हाजिर किया था। डीएम अविनाश कुमार ने मजिस्ट्रियल जांच के लिए टीम गठित की। लोगों में पुलिसकर्मियों पर हत्या का मुकदमा दर्ज नहीं होने को लेकर नाराजगी थी।

Jansatta, Lucknow, 19/09/2025
Page No: 3, Size: 6.06cm × 12.17cm

महिला को जिंदा जलाने के मामले में आयोग ने उत्तर प्रदेश सरकार से मांगा जवाब

नई दिल्ली, 18 सितंबर (ब्यूरो)।

फर्रुखाबाद जिले में एक महिला को पेट्रोल छिड़ककर जिंदा जलाने की घटना को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने गंभीरता से लिया है आयोग ने उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक और मुख्य सचिव को नोटिस जारी किया है। उनसे घटना के बारे में दो हफ्तें के भीतर विस्तृत जवाब मांगा है। आयोग ने राज्य सरकार से पूछा है कि महिला को जलाने वालों के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई और पीड़ित के परिवार जनों को कोई आर्थिक सहायता दी गई या नहीं। मीडिया में आइ खबरों के अनुसार, महिला छह सितंबर को अपनी बीमार बेटी के लिए दवा खरीदने गई थी। तभी कुछ लोगों ने उस पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी थी।

Dainik Bhaskar, Raipur, 19/09/2025
Page No: 3, Size: 8.92cm × 6.24cm

राजधानी में लावारिस लाशों के लिए जगह नहीं, मुख्य सचिव से मांगा जवाब

रायपुर | राजधानी के अंबेडकर अस्पताल शवगृह में लावारिस शव रखने और उनका अंतिम संस्कार न होने की खबर पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने स्वतः संज्ञान लिया है।

आयोग ने छत्तीसगढ़ सरकार के मुख्य सचिव को नोटिस जारी कर दो हफ्ते में विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। आयोग ने टिप्पणी करते हुए कहा कि यह मानवाधिकार का गंभीर उल्लंघन है। मृतकों को भी अपने धर्म के अनुसार सम्मानपूर्वक अंतिम संस्कार का अधिकार है। 2021 में आयोग ने परामर्श जारी कर यह स्पष्ट किया था कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन, गरिमा और सम्मान का अधिकार न केवल जीवित व्यक्तियों बल्कि मृत शरीर पर भी समान रूप से लागू होता है।

Rajasthan Patrika, Delhi, 19/09/2025
Page No: 2, Size: 17.20cm × 12.33cm

मानवाधिकार आयोग ने लिया संज्ञान

मध्यप्रदेश-छत्तीसगढ़ के सीएस को नोटिस, दो सप्ताह में जवाब तलब

मप्र में अस्पताल में खराब सेवाएं और छग में लावारिस लाशों के अंतिम संस्कार में जगह की कमी का मामला

पत्रिका ब्यूरो
patrika.com

नई दिल्ली. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिवों को नोटिस जारी किया। मध्यप्रदेश में जहां जबलपुर के बरेला में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सा सेवाओं की बेहद खराब स्थिति पर नोटिस दिया गया है। वहीं छत्तीसगढ़ में लावारिस लाशों के अंतिम संस्कार में कोताही व जगह की कमी पर नोटिस दिया गया। दोनों मामलों में दो सप्ताह में मुख्य सचिवों से जवाब मांगा गया है।

मध्यप्रदेश: जबलपुर के पीएचसी में खराब स्थिति

आयोग ने जबलपुर के बरेला में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) में चिकित्सा सेवाओं की बेहद खराब स्थिति पर स्वतः संज्ञान लिया। इसके तहत मध्य प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव को नोटिस जारी कर दो सप्ताह में विस्तृत रिपोर्ट मांगी। मीडिया में यह आया था कि स्वास्थ्य केंद्र में चार डॉक्टर तैनात हैं, लेकिन उनमें से कोई भी रात्रि पारी में ड्यूटी पर नहीं आता। मरीजों, विशेष रूप से दुर्घटनाओं में घायल लोगों को प्राथमिक उपचार और बुनियादी स्वास्थ्य देखभाल के लिए भी जिला अस्पताल रेफर किया जाता है। स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टरों की अनुपलब्धता के कारण कुछ मामलों में मरीजों की जान चली गई।

छत्तीसगढ़: रायपुर जिला अस्पताल शवगृह में लावारिस शवों का ढेर

आयोग ने अंतिम संस्कार के लिए स्थान की कमी के कारण छत्तीसगढ़ के रायपुर जिला अस्पताल शवगृह में लावारिस शवों के ढेर लगने की खबर पर स्वतः संज्ञान लिया है। इसके तहत छत्तीसगढ़ सरकार के मुख्य सचिव को नोटिस जारी कर दो सप्ताह में विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई। अंतिम संस्कार के लिए स्थान निर्धारित न किए जाने के कारण रायपुर जिला अस्पताल के शवगृह में कई लावारिस शवों के ढेर लगे होने संबंधी मीडिया में न्यूज प्रकाशित हुई थी। वहां अंतिम संस्कार एक गैर-सरकारी संगठन की ओर से किया जाता है। बताया गया है कि पिछले सप्ताह से ही तीन अज्ञात शवों को पोस्टमार्टम के लिए भी नहीं भेजा गया है। प्रशासन ने लावारिस शवों के अंतिम संस्कार के लिए लगभग तीन वर्ष पहले तीन एकड़ जमीन आवंटित की थी, जहां गैर-सरकारी संगठन की ओ से 800 से अधिक लावारिस शवों का अंतिम संस्कार किया गया। कहा जा रहा है कि मिट्टी भरकर इस भूमि का दोबारा इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन जिला प्रशासन ने इस बारे में अब तक कोई कदम नहीं उठाया।

News on Air

NHRC Issues notices to UP Police over death and injuries in Ghazipur Lathi Charge

https://www.newsonair.gov.in/nhrc-issues-notices-to-up-police-over-death-and-injuries-in-ghazipur-lathi-charge/

September 18, 2025 7:30 PM

National Human Rights Commission (NHRC) has issued notices to Uttar Pradesh Director General of Police and District Magistrate of Ghazipur over the reported death of a villager and injuries sustained by others in a police lathi charge on the 9th of this month.

According to media reports, a villager had died and some others sustained injuries in a police lathi charge while protesting against the installation of electricity poles. The commission has asked for a detailed report on the matter within two weeks. According to the media report, five police personnel have been placed under suspension after the incident.

Hindustan Times

NHRC issues notice to Chhattisgarh govt over unclaimed bodies in Raipur hospital mortuary

https://www.hindustantimes.com/india-news/nhrc-issues-notice-to-chhattisgarh-govt-over-unclaimed-bodies-in-raipur-hospital-mortuary-101758211519053.html

Sept 18, 2025 09:35 pm IST PTI

New Delhi, The NHRC on Thursday said it has issued a notice to the Chhattisgarh government over reports that several unclaimed dead bodies had piled up in the mortuary of the Raipur district hospital, as allegedly no place was allotted for their last rites.

In a statement, the National Human Rights Commission observed that the dead "also deserve last rites with dignity" in accordance with the religion they espoused.

The NHRC has "taken suo motu cognisance of a media report that a number of unclaimed dead bodies are piled up in the mortuary of the district hospital, Raipur, Chhattisgarh, as there is no place allotted for their last rites, which are being performed by an NGO", it said.

The commission also observed that the content of the media report, if true, raises a "serious issue of violation of human rights as the dead also deserve the last rights with dignity".

Three unidentified bodies allegedly have not been sent even for post-mortem examinations since last week, the statement said.

Accordingly, it has issued a notice to the chief secretary of the government of Chhattisgarh, seeking a detailed report in two weeks, the rights panel said.

The commission also issued an advisory in 2021 for upholding the dignity and protecting the rights of the dead. It said that it is a well-accepted legal position that the right to life, fair treatment and dignity, derived from Article 21 of the Constitution of India, extends not only to the living persons but also to their dead bodies.

According to the media report, carried on September 9, the district administration allocated three acres of land for the last rites of unclaimed bodies about three years ago, where the last rites of over 800 unclaimed bodies were performed by the said NGO, the statement said.

"Reportedly, the land could be reused after refilling of the soil, but no action has been taken by the district administration so far," it added.

PTI

NHRC issues notice to Chhattisgarh govt over unclaimed bodies in Raipur hospital mortuary

https://www.ptinews.com/editor-detail/NHRC-issues-notice-to-Chhattisgarh-govt-over-unclaimed-bodies-in-Raipur-hospital-mortuary/2928205

NEW DELHI: (Sep 18) The NHRC on Thursday said it has issued a notice to the Chhattisgarh government over reports that several unclaimed dead bodies had piled up in the mortuary of the Raipur district hospital, as allegedly no place was allotted for their last rites.

In a statement, the National Human Rights Commission observed that the dead "also deserve last rites with dignity" in accordance with the religion they espoused.

The NHRC has "taken suo motu cognisance of a media report that a number of unclaimed dead bodies are piled up in the mortuary of the district hospital, Raipur, Chhattisgarh, as there is no place allotted for their last rites, which are being performed by an NGO", it said.

Free Press Journal

Mumbai News: NHRC Issues Notice To BMC For Human Rights Violations Over Unsafe Manual Scavenging In M East Ward

https://www.freepressjournal.in/mumbai/mumbai-news-nhrc-issues-notice-to-bmc-for-human-rights-violations-over-unsafe-manual-scavenging-in-m-east-ward

Thursday, September 18, 2025, 07:58 PM IST Manoj Ramakrishnan

The National Human Rights Commission has issued notices to the commissioner, Brihanmumbai Municipal Corporation, district collector, commissioner of police, and the assistant municipal commissioner, M East ward, saying that the BMC is violating human rights by permitting manual scavengers to clean sewage drains with bare hands, risking their health and lives.

Mumbai: The National Human Rights Commission has issued notices to the commissioner, Brihanmumbai Municipal Corporation, district collector, commissioner of police, and the assistant municipal commissioner, M East ward, saying that the BMC is violating human rights by permitting manual scavengers to clean sewage drains with bare hands, risking their health and lives. The agencies have been asked to prepare a list of victims of manual scavenging in the ward and reply to the notice by October 24.

Complaint From Citizens' Forum

The notice was issued earlier this week in response to a complaint in April 2023 by the Govandi Citizens' Welfare Forum, seeking the commission's intervention in stopping blatant violations of laws forbidding manual scavenging, including the Prohibition of Employment of Manual Scavengers and their Rehabilitation Act, 2013.

Evidence of Unsafe Conditions

Advocate Faiyaz Alam Shaikh, convenor of the citizens' group, said they provided the commission photographs as proof that labourers were working in unsafe conditions in Kamala Rajan Nagar and Baiganwadi in M East.

Dinesh Berdia of Sangharsh, a group working for the abolition of manual scavenging and the caste-based exploitation involved in the work, said, "Govandi residents brought it to the notice of the human rights commission, but it is happening all over Mumbai. Contractors entrust the work to subcontractors who hired unorganised labourers. They do not care about the lives or health of the workers and their families," said Berdia.

BMC's Tender Process and Reality on Ground

The commission said that the BMC appoints contractors by inviting tender for desilting of minor drains, road side drains and culverts by using manpower and machinery. The contractor removes silt and floating material from minor nallahs and road-side drains by

deploying labourers and machinery as these are storm water outlets meant to carry rainwater discharge.

However, human rights activists pointed out that in Mumbai, storm water drains have become sewage lines, with illegal discharge of domestic and industrial waste.

NHRC Rejects BMC Safety Claims

In an earlier reply, the BMC had told the commission that desilting is done by manpower with safety gears, such as hand gloves, helmets, reflecting jackets, safety shoes, with contractors penalised for lapses. In case the drains are difficult for cleaning equipment to access, contractors use labourers, but under precautions and safety advice of a medical officer.

The commission debunked the claims, saying that labourers were found cleaning gutters with bare hands and the concerned authorities failed to explain this in their report dated August 25, 2023. The commission further stated that even if it was the contractors who employed labourers for cleaning the gutters, it does not absolve the principal employer - the BMC - of their liability for safeguarding the manual scavengers.

Pending Response Could Lead to Coercive Action

The commission said that there appears to be a violation of the 2013 law. The commission said the M East ward has not replied to its show cause notice in May 2024, as to why a compensation of Rs 50,000 each should not be given to manual scavengers for violation of their human rights. The commission said that failure to reply to the notice will lead to coercive process under the Protection of Human Rights Act, 1993.

Orrisa Diary

NHRC, India takes suo motu cognizance of the reported burning of a woman by a group of people in Farrukhabad district, Uttar Pradesh

https://orissadiary.com/nhrc-india-takes-suo-motu-cognizance-of-the-reported-burning-of-a-woman-by-a-group-of-people-in-farrukhabad-district-uttar-pradesh/

September 18, 2025 Bureau

The National Human Rights Commission (NHRC), India has taken suo motu cognizance of a media report that a woman was doused with petrol and burnt alive by a group of people in Farrukhabad district, Uttar Pradesh on 6th September, 2025. The victim had gone out to buy medicine for her daughter when she was assaulted. Later, she succumbed to her injuries at a hospital.

The Commission has examined the contents of the news report, if true, raise a serious issue of human rights violations. Therefore, it has issued notices to the Chief Secretary and the Director General of Police, Uttar Pradesh, calling for a detailed report on the matter within two weeks.

The report is expected to include the action taken against the perpetrators and compensation, if any, provided to the next of kin (NOK) of the deceased.

Lokmat Times

NHRC takes suo motu cognisance of doctor shortage at ESIC hospital in Faridabad

https://www.lokmattimes.com/national/nhrc-takes-suo-motu-cognisance-of-doctor-shortage-at-esic-hospital-in-faridabad/

September 19, 2025 01:10 IST

New Delhi, Sep 19 The National Human Rights Commission (NHRC) has taken suo motu cognisance of a media...

New Delhi, Sep 19 The National Human Rights Commission (NHRC) has taken suo motu cognisance of a media report highlighting difficulties faced by patients due to the lack of doctors and infrastructure at the super speciality ESIC hospital in Haryana's Faridabad.

According to the press report, more than 6.5 lakh ESIC cardholders from Palwal and Faridabad, along with patients from Delhi, Noida, and Gurugram, depend on the hospital for treatment of serious ailments related to heart, cancer, neurology, and intestinal infections.

Patients reportedly have to wait for several hours even in the emergency ward.

The report further stated that the Cardiology department has been without a doctor for the past month, and specialist doctors are engaged on a part-time basis.

The Dean of the ESIC Medical College has reportedly admitted that there are currently no specialist doctors available in the hospital. Taking note of the report, the apex human rights body observed that the contents, if true, raise serious concerns of human rights violations.

The NHRC has issued notices to the Haryana Chief Secretary and the Chairman o the Employees' State Insurance Corporation (ESIC), seeking a detailed report on the matter within two weeks.

Established under the Protection of Human Rights Act, 1993, the NHRC, an autonomous statutory body, is an embodiment of India's concern for the promotion and protection of human rights.

Its primary role is to protect and promote human rights, defined as the rights relating to life, liberty, equality, and dignity of individuals guaranteed by the Constitution or embodied in international covenants and enforceable by courts in India.

The apex human rights body has the power to take suo motu (on its own motion) action based on media reports, public knowledge or other sources, without receiving a formal complaint of human rights violations.

Lokmat Times

NHRC seeks report on 'very bad condition' of govt health centre in MP's Jabalpur

https://www.lokmattimes.com/national/nhrc-seeks-report-on-very-bad-condition-of-govt-health-centre-in-mps-jabalpur/

September 19, 2025 00:00 IST

New Delhi, Sep 18 The National Human Rights Commission (NHRC) has taken suo motu cognisance of a media...

New Delhi, Sep 18 The National Human Rights Commission (NHRC) has taken suo motu cognisance of a media report highlighting "very bad condition" of a government-run primary health centre (PHC) at Barela in Madhya Pradesh's Jabalpur.

According to the press report, although four doctors are posted at the health centre, none reportedly attend duty during the night.

Patients, particularly those injured in accidents, are often referred to the District Hospital even for first aid and basic treatment.

In some instances, the absence of doctors at the PHC has reportedly resulted in the loss of lives.

The report also said that the lack of night-time medical services makes it impossible to conduct medico-legal examinations for accident victims.

Police officials bringing patients for medico-legal examinations are forced to take them to the District Hospital, causing delays and unnecessary inconvenience in providing lifesaving treatment.

Taking note of the report, the apex human rights body said that the contents, if true, raise serious concerns of human rights violations.

The NHRC has issued a notice to the Madhya Pradesh Chief Secretary seeking a detailed report on the matter within two weeks.

Established under the Protection of Human Rights Act, 1993, the NHRC, an autonomous statutory body, is an embodiment of India's concern for the promotion and protection of human rights.

Its primary role is to protect and promote human rights, defined as the rights relating to life, liberty, equality, and dignity of individuals guaranteed by the Constitution or embodied in international covenants and enforceable by courts in India.

The apex human rights body has the power to take suo motu (on its own motion) action based on media reports, public knowledge or other sources, without receiving a formal complaint of human rights violations.

Sakshi Post

NHRC takes suo motu cognisance of unclaimed bodies piling up in Raipur mortuary

https://www.sakshipost.com/news/nhrc-takes-suo-motu-cognisance-unclaimed-bodies-piling-raipur-mortuary-454060

Sep 19, 2025, 00:25 IST

New Delhi, Sep 19 (IANS) The National Human Rights Commission (NHRC) has taken suo motu cognisance of a media report that a number of unclaimed dead bodies are reportedly piled up in the mortuary of the Raipur District Hospital in Chhattisgarh, due to the lack of space for their last rites.

The report states that an NGO has been performing the funerals, while three unidentified bodies have not even been sent for post-mortem examinations since last week.

Taking note of the report, the apex human rights body observed that the contents, if true, raise serious concerns of human rights violations, as the dead also deserve to be treated with dignity and in accordance with their religion.

The NHRC has issued a notice to the Chhattisgarh Chief Secretary, seeking a detailed report on the matter within two weeks.

The Commission had previously issued an advisory in 2021 emphasizing the need to uphold the dignity and protect the rights of the dead. It noted that the right to life, fair treatment, and dignity under Article 21 of the Constitution of India extends not only to living persons but also to their dead bodies.

According to the press report, the district administration had allocated three acres of land for the last rites of unclaimed bodies about three years ago, where the last rites of over 800 unclaimed bodies were performed by the NGO.

The land could reportedly be reused after refilling of the soil, but no action has been taken by the administration so far.

Established under the Protection of Human Rights Act, 1993, the NHRC, an autonomous statutory body, is an embodiment of India's concern for the promotion and protection of human rights.

Its primary role is to protect and promote human rights, defined as the rights relating to life, liberty, equality, and dignity of individuals guaranteed by the Constitution or embodied in international covenants and enforceable by courts in India.

The apex human rights body has the power to take suo motu (on its own motion) action based on media reports, public knowledge or other sources, without receiving a formal complaint of human rights violations.

Sakshi Post

NHRC seeks reply in 2 weeks from UP govt on 'burning' of woman in Farrukhabad

https://www.sakshipost.com/news/nhrc-seeks-reply-2-weeks-govt-burning-woman-farrukhabad-453883

Sep 18, 2025, 17:00 IST

New Delhi, Sep 18 (IANS) The National Human Rights Commission (NHRC) has sought a report within two weeks from the Uttar Pradesh government and the state police chief over a woman being allegedly doused with petrol and burnt alive by a group of people in Farrukhabad district, an official said on Thursday.

The NHRC issued the direction after taking suo motu cognizance of a media report over the September 6 incident, said the official in a statement.

According to the media report, the victim had gone out of her home to buy medicine for her daughter when she was assaulted. Later, she succumbed to her injuries at a hospital.

"The Commission has examined the contents of the news report, if true, raise a serious issue of human rights violations. Therefore, it has issued notices to the Chief Secretary and the Director General of Police, Uttar Pradesh, calling for a detailed report on the matter within two weeks," said the NHRC official in a statement.

The government and police chief's report is expected to include the action taken against the perpetrators and compensation, if any, provided to the next of kin of the deceased, it said.

In a separate case, the NHRC sought a reply within two weeks from Chhattisgarh government after taking suo motu cognizance of a media report that a number of unclaimed dead bodies had piled up in the mortuary of the District Hospital, Raipur, Chhattisgarh as there is no place allotted for their last rites.

The media report said that the responsibility for cremations is allotted to the NGO. Reportedly, three unidentified bodies had not even been sent for post-mortem examinations since last week, said statement.

"The contents of the media report, if true, raise a serious issue of violation of human rights as the dead also deserve the last rights with dignity in accordance with their religion. Accordingly, it has issued a notice to the Chief Secretary, Government of Chhattisgarh, seeking a detailed report on the matter within two weeks," it said.

The Commission had also issued an advisory in 2021 for upholding the dignity and protecting the rights of the dead. It said that it is a well-accepted legal position that the

right to life, fair treatment and dignity, derived from the Article 21 of the Constitution of India, extends not only to the living persons but also to the dead.

According to the media report, carried on September 9, 2025, the district administration had allocated three acres of land for the last rites of unclaimed bodies about three years ago, where the last rites of over 800 unclaimed bodies were performed by the said NGO.

Reportedly, the land could be re-used after refilling of the soil, but no action has been taken by the district administration so far.

News X

Chhattisgarh: NHRC takes suo motu cognizance of piling up of unclaimed dead bodies in Raipur hospital

https://www.newsx.com/india/chhattisgarh-nhrc-takes-suo-motu-cognizance-of-piling-up-of-unclaimed-dead-bodies-in-raipur-hospital20250918190101-73394/amp/

September 18, 2025 19:08:07 IST

New Delhi [India], September 18 (ANI): The National Human Rights Commission (NHRC), India has taken suo motu cognisance of a media report that a number of unclaimed dead bodies are piled up in the mortuary of the District Hospital, Raipur, Chhattisgarh, as there is no place allotted for their last rites, which are being performed by an NGO, according to an official press release.

Reportedly, three unidentified bodies have not been sent even for post-mortem examinations since last week, the release said.

The Commission has observed that the contents of the media report, if true, raise a serious issue of violation of human rights, as the dead also deserve the last rites with dignity in accordance with their religion. Accordingly, it has issued a notice to the Chief Secretary, Government of Chhattisgarh, seeking a detailed report on the matter within two weeks.

The Commission had also issued an advisory in 2021 for upholding the dignity and protecting the rights of the dead. It said that it is a well-accepted legal position that the right to life, fair treatment and dignity, derived from Article 21 of the Constitution of India, extends not only to the living persons but also to their dead bodies, the release said.

According to the media report, carried on September 9, the district administration had allocated three acres of land for the last rites of unclaimed bodies about three years ago, where the last rites of over 800 unclaimed bodies were performed by the said NGO. Reportedly, the land could be reused after refilling of the soil, but no action has been taken by the district administration so far, the release stated. (ANI)

Sakshi Post

NHRC seeks report on 'very bad condition' of govt health centre in MP's Jabalpur

https://m.sakshipost.com/amp/news/nhrc-seeks-report-very-bad-condition-govt-health-centre-mps-jabalpur-454053

19 Sep, 2025 00:00 IST

New Delhi, Sep 18 (IANS) The National Human Rights Commission (NHRC) has taken suo motu cognisance of a media report highlighting "very bad condition" of a government-run primary health centre (PHC) at Barela in Madhya Pradesh's Jabalpur.

According to the press report, although four doctors are posted at the health centre, none reportedly attend duty during the night.

Patients, particularly those injured in accidents, are often referred to the District Hospital even for first aid and basic treatment.

In some instances, the absence of doctors at the PHC has reportedly resulted in the loss of lives.

The report also said that the lack of night-time medical services makes it impossible to conduct medico-legal examinations for accident victims.

Police officials bringing patients for medico-legal examinations are forced to take them to the District Hospital, causing delays and unnecessary inconvenience in providing lifesaving treatment.

Taking note of the report, the apex human rights body said that the contents, if true, raise serious concerns of human rights violations.

The NHRC has issued a notice to the Madhya Pradesh Chief Secretary seeking a detailed report on the matter within two weeks.

Established under the Protection of Human Rights Act, 1993, the NHRC, an autonomous statutory body, is an embodiment of India's concern for the promotion and protection of human rights.

Its primary role is to protect and promote human rights, defined as the rights relating to life, liberty, equality, and dignity of individuals guaranteed by the Constitution or embodied in international covenants and enforceable by courts in India.

The apex human rights body has the power to take suo motu (on its own motion) action based on media reports, public knowledge or other sources, without receiving a formal complaint of human rights violations.

Disclaimer: This story has not been edited by the Sakshi Post team and is auto-generated from syndicated feed.

The Print

एनएचआरसी ने रायपुर अस्पताल के शवगृह में पड़े लावारिस शवों पर छत्तीसगढ़ सरकार को नोटिस भेजा

https://hindi.theprint.in/india/nhrc-issues-notice-to-chhattisgarh-government-over-unclaimed-bodies-lying-in-raipur-hospital-mortuary/870530/?amp

18 September, 2025 Rakhi Sureah

नयी दिल्ली, 18 सितंबर (भाषा) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने बृहस्पतिवार को छत्तीसगढ़ सरकार को उस मीडिया रिपोर्ट के आधार पर नोटिस जारी किया है, जिनमें दावा किया गया था कि रायपुर जिला अस्पताल के शवगृह में कई लावारिस शव पड़े हैं, क्योंकि उनके अंतिम संस्कार के लिए कथित तौर पर कोई जगह निर्धारित नहीं की गई है।

आयोग ने एक बयान में कहा कि “मृतकों को भी उनकी आस्था के अनुसार गरिमा के साथ अंतिम संस्कार का अधिकार है।”

एक बयान के अनुसार, एनएचआरसी ने मीडिया रिपोर्ट के आधार पर स्वत: संज्ञान लिया है।

आयोग ने कहा कि यदि मीडिया रिपोर्ट का कंटेंट सही है तो “यह मानवाधिकार उल्लंघन का गंभीर मामला है, क्योंकि मृतकों को भी गरिमामय अंतिम संस्कार का अधिकार है।”

बयान में कहा गया कि पिछले सप्ताह से तीन अज्ञात शव को कथित तौर पर पोस्टमार्टम के लिए भी नहीं भेजा गया है।

आयोग ने छत्तीसगढ़ सरकार के मुख्य सचिव को नोटिस जारी कर दो सप्ताह में विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।

आयोग ने यह भी कहा कि 2021 में उसने मृतकों की गरिमा और अधिकारों की रक्षा के लिए एक परामर्श जारी किया था।

परामर्श के अनुसार, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 से प्राप्त जीवन, न्यायपूर्ण व्यवहार और गरिमा का अधिकार न केवल जीवित व्यक्तियों, बल्कि उनके शव तक भी विस्तारित होता है।

बयान में बताया गया कि मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, नौ सितंबर को प्रकाशित खबर में बताया गया था कि जिला प्रशासन ने लगभग तीन साल पहले लावारिस शवों के अंतिम संस्कार के लिए तीन एकड़ भूमि आवंटित की थी, जहां एक गैर-सरकारी संगठन द्वारा 800 से अधिक शवों का अंतिम संस्कार किया जा चुका है।

रिपोर्ट में कहा गया कि ‘उक्त भूमि को मिट्टी भरकर फिर से उपयोग में लाया जा सकता था, लेकिन अब तक जिला प्रशासन ने इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की है।’

IBC 24

एनएचआरसी ने रायपुर अस्पताल के शवगृह में पड़े लावारिस शवों पर छत्तीसगढ़ सरकार को नोटिस भेजा

https://www.ibc24.in/country/nhrc-sends-notice-to-chhattisgarh-govt-over-unclaimed-bodies-lying-in-mortuary-of-raipur-hospital-3258355.html

September 18, 2025 10:30 pm IST Rakhi Shuresh

नयी दिल्ली, 18 सितंबर (भाषा) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने बृहस्पतिवार को छत्तीसगढ़ सरकार को उस मीडिया रिपोर्ट के आधार पर नोटिस जारी किया है, जिनमें दावा किया गया था कि रायपुर जिला अस्पताल के शवगृह में कई लावारिस शव पड़े हैं, क्योंकि उनके अंतिम संस्कार के लिए कथित तौर पर कोई जगह निर्धारित नहीं की गई है।

आयोग ने एक बयान में कहा कि “मृतकों को भी उनकी आस्था के अनुसार गरिमा के साथ अंतिम संस्कार का अधिकार है।”

एक बयान के अनुसार, एनएचआरसी ने मीडिया रिपोर्ट के आधार पर स्वत: संज्ञान लिया है।

आयोग ने कहा कि यदि मीडिया रिपोर्ट का कंटेंट सही है तो “यह मानवाधिकार उल्लंघन का गंभीर मामला है, क्योंकि मृतकों को भी गरिमामय अंतिम संस्कार का अधिकार है।”

बयान में कहा गया कि पिछले सप्ताह से तीन अज्ञात शव को कथित तौर पर पोस्टमार्टम के लिए भी नहीं भेजा गया है।

आयोग ने छत्तीसगढ़ सरकार के मुख्य सचिव को नोटिस जारी कर दो सप्ताह में विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।

आयोग ने यह भी कहा कि 2021 में उसने मृतकों की गरिमा और अधिकारों की रक्षा के लिए एक परामर्श जारी किया था।

परामर्श के अनुसार, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 से प्राप्त जीवन, न्यायपूर्ण व्यवहार और गरिमा का अधिकार न केवल जीवित व्यक्तियों, बल्कि उनके शव तक भी विस्तारित होता है।

बयान में बताया गया कि मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, नौ सितंबर को प्रकाशित खबर में बताया गया था कि जिला प्रशासन ने लगभग तीन साल पहले लावारिस शवों के अंतिम संस्कार के लिए तीन एकड़ भूमि आवंटित की थी, जहां एक गैर-सरकारी संगठन द्वारा 800 से अधिक शवों का अंतिम संस्कार किया जा चुका है।

रिपोर्ट में कहा गया कि ‘उक्त भूमि को मिट्टी भरकर फिर से उपयोग में लाया जा सकता था, लेकिन अब तक जिला प्रशासन ने इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की है।’

Hindustan

मानवाधिकार आयोग पहुंचा पुलिस दबिश में किसान की मौत का मामला

https://www.livehindustan.com/uttar-pradesh/badaun/story-police-misconduct-leads-to-innocent-farmer-s-death-in-binawar-human-rights-commission-involved-201758235086378.html

Fri, 19 Sep 2025 04:08 AM

Badaun News - बिनावर थाना क्षेत्र के सेमरमई गांव में पुलिस की दबिश के दौरान शाकिर की मौत हो गई। कांग्रेस जिलाध्यक्ष अजीत यादव ने आयोग से शिकायत की कि यह पुलिस की लापरवाही और उत्पीड़न का परिणाम है। शाकिर निर्दोष था...

बिनावर थाना क्षेत्र के सेमरमई गांव में पुलिस दबिश के दौरान शाकिर की मौत का मामला राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग तक पहुंच गया है। कांग्रेस जिलाध्यक्ष अजीत यादव ने आयोग को शिकायत भेजते हुए कहा कि निर्दोष ग्रामीण की मौत पुलिस की लापरवाही और उत्पीड़न का नतीजा है। शिकायत में बताया गया कि 15/16 सितंबर की रात करीब 12 बजे गोकश सत्यापन के लिए पहुंची बिनावर पुलिस ने गांव में घर के बाहर सो रहे शाकिर को दौड़ाया। घबराकर वह धान के खेत में गिर पड़ा और उसकी मौत हो गई। अजीत यादव ने कहा कि शाकिर का कोई आपराधिक इतिहास नहीं था, उस पर किसी थाने में कोई मुकदमा दर्ज नहीं था।

वह दो-तीन बीघा जमीन पर खेती और मजदूरी कर अपने तीन बच्चों का पेट पाल रहा था। पत्नी पहले ही गुजर चुकी थी, अब बच्चे अनाथ हो गए हैं। कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने आयोग से इस पूरे मामले की न्यायिक जांच, दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई और पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपये मुआवजा दिलाने की मांग की है।

Amar Ujala

Budaun News: मानवाधिकार आयोग तक पहुंचा शाकिर की मौत का मामला

https://www.amarujala.com/uttar-pradesh/budaun/the-case-of-shakirs-death-reached-the-human-rights-commission-badaun-news-c-123-1-bdn1012-147275-2025-09-19

Fri, 19 Sep 2025 02:01 AM IST Burea

बदायूं। बिनावर थाना क्षेत्र के सेमरमई गांव में पुलिस की दबिश के दौरान शाकिर की मौत का मामला राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग तक पहुंच गया है। कांग्रेस जिलाध्यक्ष अजीत यादव ने इस प्रकरण की शिकायत आयोग से की है। साथ ही न्याय और मुआवजा की मांग की है।

उन्होंने बताया कि 15 सितंबर की रात बिनावर पुलिस गो तस्करों को पकड़ने के लिए सेमरमई में दबिश दी थी। इसी दौरान पुलिस ने घर के बाहर सो रहे शाकिर को दौड़ाया। इससे वह वह धान के खेत में गिर पड़ा और उसकी मौत हो गई। बताया कि शाकिर पर किसी थाने में मुकदमा दर्ज नहीं था और न ही उसका कोई आपराधिक इतिहास था। वह दो-तीन बीघा ज़मीन का मालिक था और मेहनत-मज़दूरी करके अपने तीन बच्चों का पालन-पोषण करता था। पत्नी के न होने से अब उसके बच्चे अनाथ हो गए हैं। उन्होंने मानवाधिकार आयोग से इस मामले की न्यायिक जांच कराए जाने, दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई किए जाने और शाकिर के परिवार को 50 लाख रुपये मुआवज़ा देने की मांग की है।

1st Bihar

मुजफ्फरपुर: कॉलेज प्राचार्या पर महिला कर्मी की पिटाई और वसूली का आरोप, मानवाधिकार आयोग पहुंचा मामला

https://firstbihar.com/bihar/muzaffarpur-news/muzaffarpur-college-principal-assault-woman-staff-human-rights-417728

Thu, 18 Sep 2025 08:58:18 PM IST Manoj Kumar

मुजफ्फरपुर के विष्णुदेव नारायण सिंह इंटर कॉलेज में प्राचार्या पर महिला कर्मी की पिटाई और दो लाख रुपए माँगने का आरोप, मामला पहुँचा मानवाधिकार आयोग।

MUZAFFARPUR: मुजफ्फरपुर के विष्णुदेव नारायण सिंह इंटर कॉलेज की प्राचार्या कुमारी दीप्ती ने अपने कॉलेज के पूर्व कर्मी कामाख्या नारायण सिंह के साथ मिलकर अपने ही कॉलेज के चतुर्थ वर्गीय कर्मी कुमारी शबनम की जमकर कुटाई कर दी। कुमारी शबनम को इतनी बेरहमी से मारा गया की उसका ईलाज बोचहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हुआ और बेहतर ईलाज के लिए चिकित्सको ने उसे एसकेएमसीएच रेफर कर दिया तब महिला का ईलाज हुआ।

बताते चले की जिले के रामपुर हरि थाना क्षेत्र के नरमा स्थित विष्णुदेव नारायण सिंह इंटर कॉलेज में चतुर्थ वर्गीय कर्मी के रूप में कुमारी शबनम कार्य करती हैं। कुमारी शबनम को कॉलेज के प्राचार्या द्वारा दो लाख रूपये की माँग की जा रही हैं और न देने पर कॉलेज से बर्खास्त करने की धमकी दी जाती हैं। शबनम ने दो लाख रूपये देने से मना कर दी,इसी बात पर प्राचार्या कुमारी दीप्ती खफा चल रह रही थी। शबनम का कहना हैं की वह कॉलेज में बीते 16 सितम्बर को गई थी तो उसे प्राचार्या के कक्ष में बुलाया गया जहाँ पर कॉलेज के पूर्व कर्मी कामाख्या नारायण सिंह बैठे हुए थे,जब शबनम प्राचार्या के कक्ष में पहुँची तो प्राचार्या अपने कक्ष से निकल गई उसके बाद कामाख्या नारायण सिंह ने गलत नियत से शबनम के साड़ी का पल्लू खींच दिया और बदतमीजी करना चाहा जिसका विरोध शबनम के द्वारा किया गया।

उसके बाद कामाख्या नारायण सिंह ने शबनम को मारने पीटने लगा।तब प्राचार्या भी अपने कक्ष में आ गई और दोनों ने मिलकर शबनम को बेरहमी से पीटने लगे। शबनम का आरोप हैं की प्राचार्या कुमारी दीप्ती और कामाख्या नारायण सिंह ने शबनम के सिर पर लोहे के रड से प्रहार किया जिससे वह घायल हो गई। अचेतावस्था में उसे आनन फानन में बोचहाँ के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया लेकिन चिकित्सको ने बेहतर ईलाज हेतु उसे एसकेएमसीएच मे रेफर कर दिया। एसकेएमसीएच मे शबनम का बेहतर ईलाज हुआ उसके बाद वह सीधे रामपुर हरि थाना गई और प्राथमिकी हेतु आवेदन दी लेकिन पुलिस के द्वारा अभी तक प्राथमिकी भी अंकित नहीं किया गया हैं।

मामले को लेकर पीड़िता ने मानवाधिकार मामलों के अधिवक्ता एस.के.झा से मिली और उनके माध्यम से राज्य मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राज्य महिला आयोग,राष्ट्रीय महिला आयोग,डीएम,एसएसपी सहित सभी सरकारी कार्यालयों को आवेदन दी। मामले के संबंध मे मानवाधिकार अधिवक्ता एस.के.झा ने बताया की यह मामला काफ़ी गंभीर हैं और महिला काफ़ी डरी व घबराई हुई हैं, इनके सिर पर चोट के निशान ईस बात को स्पष्ट करता हैं की इनके साथ काफ़ी बेरहमी से मारपीट की गई हैं।पुलिस के द्वारा अभी तक दोषियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज नहीं किया जाना काफ़ी दुःखद हैं।

NDTV

मेडिकल कॉलेज अस्पताल में मरीजों को चूहों ने काटा, मानवाधिकार आयोग ने लिया संज्ञान, ठेका कंपनी पर जुर्माना

https://mpcg.ndtv.in/madhya-pradesh-news/jabalpur-medical-college-hospital-patients-were-bitten-by-rats-the-human-rights-commission-took-note-9298205

सितंबर 18, 2025 09:35 am IST Ambuj Sharma

MP News: मेडिकल कॉलेज में पेस्ट कंट्रोल पर हर साल करीब 5 लाख रुपये खर्च किए जाते हैं. इसके बावजूद चूहों द्वारा मरीजों को काटने की घटनाएं सामने आ रही हैं.

Madhya Pradesh News: मध्य प्रदेश के जबलपुर के नेताजी सुभाषचंद्र बोस मेडिकल कॉलेज अस्पताल में मरीजों और अटेंडर को चूहों द्वारा काटे जाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है. हाल ही में मनोरोग विभाग के वार्ड में भर्ती सिहोरा निवासी 25 वर्षीय युवती, श्रीधाम निवासी 50 वर्षीय महिला और उसका बेटा चूहों के हमले का शिकार हुए थे.

युवती को 9 सितंबर की रात को पैर में काटा गया, उपचार के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया. वहीं, महिला की एड़ी और अगले दिन उसके बेटे के पैरों पर भी चूहों ने हमला कर दिया.

शिकायत के बाद भी ध्यान नहीं

परिजनों का कहना है कि बार-बार शिकायत करने के बावजूद अस्पताल प्रबंधन ने कोई ठोस इंतजाम नहीं किए. मामला मीडिया में आने के बाद मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग ने भी स्वतः संज्ञान लिया. आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष राजीव कुमार टंडन की एकल पीठ ने प्रथम दृष्टया इसे मानवाधिकार हनन का मामला मानते हुए मेडिकल कॉलेज के डीन से जांच कराकर एक माह में प्रतिवेदन मांगा है.

इधर, मेडिकल कॉलेज प्रबंधन ने कार्रवाई करते हुए पेस्ट कंट्रोल करने वाली ठेका कंपनी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया और कंपनी के सुपरवाइजर से जवाब-तलब किया है. साथ ही अस्पताल अधीक्षक ने तीन सदस्यीय जांच समिति गठित की है, जो तीन दिनों में रिपोर्ट सौंपेगी.

गौरतलब है कि मेडिकल कॉलेज में पेस्ट कंट्रोल पर हर साल करीब 5 लाख रुपये खर्च किए जाते हैं. इसके बावजूद चूहों द्वारा मरीजों को काटने की घटनाएं सामने आ रही हैं. विशेषज्ञों का कहना है कि दशकों पुराने भवनों में चूहों का स्थायी रहवास, मरीजों के परिजनों द्वारा वार्डों में भोजन ले जाना, परिसर में जगह-जगह खाना बनाना और वॉर्डों के पीछे मौजूद गंदगी इसकी मुख्य वजह है.

कलेक्टर ने कार्रवाई के दिए निर्देश

कलेक्टर राघवेंद्र सिंह ने भी घटना के बाद मनोरोग विभाग का निरीक्षण किया और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए. प्रबंधन ने आश्वासन दिया है कि चूहों के प्रवेश मार्गों पर विशेष ध्यान देकर ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने की कोशिश की जाएगी.